GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜ਼ਂ. 99] No. 99] दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2015/श्रावण 9, 1937

DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2015/SRAVANA 9, 1937

[रा.स.स.क्षे.दि. सं. 75 [N.C.T.D. No. 75

भाग---!\

PART--IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

> वित्त (राजस्व-1) विमाग अधिसूचना

दिल्ली, 31 जुलाई, 2015

सं.फा.03(11)/वित्त (राजस्व-1)/2015-16/डीएस-VI/599.-जबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का अभिमत है कि ऐसा करना जनसाधारण के हित में समीचीन है।

इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा उक्त अधिनियत से संलग्न अनुसूचियों में निम्नांकित संशोधन करते हैं, अर्थात् :--

संशोधन

दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3), (जिसके यहां इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" में संदर्भित) से संलग्न तृतीय अनुसूची में –

(क) क्रमांक 06 की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--

"06 मूल्यवान धातुओं से बने हुए के अतिरिक्त धातुओं से बने सभी प्रकार के बरतन तथा छुरी—कांटे (प्रेशर कुकर/पैन सम्मिलित)";

- (ख) क्रमांक 120 की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--
 - "120 किसी अनुसूची की किसी अन्य प्रविष्टि में न आने वाले सभी प्रकार के वैक्स";
- (ग) क्रमांक 169 पर निम्नलिखित प्रविष्टि सन्निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :-"169 लकड़ी तथा टिम्बर."।

यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में 1 अगस्त, 2015 की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम से

ए.के.सिंह, उपसचिव-VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 31st July, 2015

F.3(11)/Fin(Rev-I)/2015-2016/dsvi/599.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following amendments in the Third Schedule appended to the said Act, namely:-

AMENDMENTS

In the Third Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005),

- (a) for the entry at Sl. No. 6, the following entry shall be substituted, namely:-
- "6. All utensils and cutlery items made of metals (including pressure cookers/pans) except those made of precious metals.";
- (b) for the entry at SI.No.120, the following entry shall be substituted, namely:-
- "120. Wax of all kinds not covered by any other entry of any schedule.";
- (c) the following entry shall be inserted at Sl. No. 169, namely:-
- "169.Wood and Timber"

This notification shall come into force with effect from 1st August, 2015.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, A.K.SINGH, Dy. Secy-VI (Finance)

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग अधिसूचनाएं

दिल्ली, 31 जुलाई, 2015

सं.फा. 27/5/01—न्याय/Suptlaw/670—673 :—निम्नलिखित को सामान्य जनसूचना के लिए, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है:—

अद्यतन यथा संशोधित विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 में बनाए गये उपबंधों के साथ पठित दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण नियमावली, 1996 के नियम 3 के अनुसरण में एवं अधिसूचना संठफांठ 27/5/01—न्याय/अधी.विधि/304—307 दिनांक: 03.03.2014 के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के लिए पदेन सदस्यों को छोड़कर निम्नलिखित सदस्यों को 02.03.2016 तक नामित करते हैं:—

क्रम सं0	व्यक्ति का नाम	पता	
1	डा० राजेश कुमार, कार्यकारी निदेशक, एस०पी०वाई०एम०		
2	श्री सिद्धार्थ लूथरा, अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल	सी-2, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली	
3	सुश्री भारती अली, सह संस्थापक हक, (बाल अधिकार केन्द्र)	बी-1/2, भूतल, मालवीय नगर, नई दिल्ली17	
4	डा० एम० अफजल वानी, प्रोफेसर और डीन, कानून एवं कानूनी अध्ययन स्कूल विश्वविद्यालय	जी०जी०एस० इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, खंड 16—सी द्वारका, नई दिल्ली—110078	
5	डा० कहकशां वाई० दनयाल, एसोसिएट प्रोफेसर, जामिया मिलिया इस्लामिया	176/21, द्वितीय तल, जाकिर नगर, ओखला, नई दिल्ली—110025	

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS **NOTIFICATIONS**

Delhi, the 31st July, 2015

No.F.27/5/01-Judl./Suptlaw/670-673.—The following is hereby published for general information of the public: -

In pursuance of the provisions contained in Section 6 of the Legal Service Authorities Act, 1987 as amended up to date read with rule 3 of the Delhi Legal Services Authorities Rules, 1996 and in supersession of Notification No. F.27/5/01-Judl/Suptlaw/304-307 dated 03.03.2014, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Delhi, is pleased to nominate the following Members other than Ex-Officio members for the Delhi State Legal Services Authority upto 02.03.2016: -

S.No	Name of the person		
1	Dr. Rajesh Kumar, Executive Director, SPYM	Address 111/9, Opp. Sector B 4, Vasant Kunj, New Delhi 110070 C-2, Defence Colony, New Delhi	
Z .	Sh. Sidharth Luthra, Addl. Solicitor General		
3	Ms. Bharti Ali Co-founder HAQ (Centre of Child Rights)	7.10	
		B-1/2, Ground Floor, Malviya Nagar, New Delh	
4	Dr. M. Afzal Wani	17	
	Professor and Dean University School of Law & Legal	GGS Indraprastha University, Sector-16-C	
ĺ	Studies Studies	Dwarka, New Delhi-110078	
5	Dr. Kahkashan Y. Danyal, Associate Professor, Jamia Millia Islamia		
		176/21, 2nd Floor, Zakir Nagar, Okhla, Nev Delhi-110025	

दिल्ली, 31 जुलाई, 2015

सं.फा 6/29/2011—न्याय/Suptlaw/663-668:-अद्यतन यथा संशोधित दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली 1970 के नियम 18 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, श्री अनुज कुमार सिंह, शारीरिक विकलांग(ऑथॉ)को दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त किए जाने पर अपने कार्यालय में कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा आधार पर दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

- उपर्युक्त नियुक्ति निशक्त व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अनुभाग 36 के प्रावधानों के तहत विकलांग(अंधता / कमदृष्टि) व्यक्तियों के प्रवर्ग के लिए आरक्षित एक खाली पद को विकलांग (ऑथॉ) के प्रवर्ग में परस्पर परिवर्तन द्वारा की गई है।
- उपर्युक्त नियुक्ति पूर्ण तया अस्थायी आधार पर हैं तथा अभ्यर्थी के विकलांगता प्रमाणपत्र के अनुसार होगी। यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि शारीरिक रूप से अपंग कोटि से संबंधित दावा गलत है तो बिना किसी आगामी कारणों तथा असत्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन की जाने वाली आगामी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेवाँ तुरन्त समाप्त कर दी जाएगी।
- उपर्युक्त नियुक्ति अद्यतन तिथि तक तथा समय-समय पर दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर यथा लागू अन्य आदेशों / निर्देशों के अनुसार दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के **उपबं**धों के अनुसार होगी।
- 5. दिल्ली न्यायिक सेवा में तथा उपर्युक्त अभ्यर्थी की परस्पर वरिष्ठता अन्य चुने गए अभ्यर्थियों के समान वहीं रहेगी जो अद्यतन तिथि तक यथा संशोधित दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के अनुसार चयन समिती द्वारा तैयार वरीयता सूची में उन्हें
- पद 27700--770--33090--920--40450--1080--44770 रूपये + सामान्य भत्ते जैसा समय--समय पर इस संबंध में लागू हो के

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर आर० किरण नाथ, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

Delhi, the 31st July, 2015

No.F.6/29/2011-Judl./Suptlaw/663-668.- In pursuance of the provisions of Rule 18 of the Delhi Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi, is pleased to appoint Sh. Anuj Kumar Singh, PH (Ortho) as member of the Delhi Judicial Service on probation for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office on being posted by the Delhi High Court, New Delhi.

- 2. The above appointment has been made by inter-changing one unfilled post reserved for category of disabled person (blind/low vision) to the category of disabled person (Ortho) under the provisions of the Section 36 of the Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.
- 3. The above appointment is on purely provisional basis, and subject to the verification of his PH category certificate. If the verification reveals that the claim to belong to Physically Handicapped category is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificate.
- 4. The above appointment shall be subject to the provisions of the Delhi Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date and other orders/instructions as may be applicable to the officers of the Delhi Judicial Service from time to time.
- 5. The inter-se seniority of the above named candidate in the Delhi Judicial Service vis-à-vis other selected candidates will remain the same as assigned to him in the merit list prepared by the Selection Committee in accordance with the provisions of the Delhi Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date.
- 6. The post carries the pay scale of Rs. 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 plus usual allowances as may be applicable in this behalf from time to time.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National

Capital Territory of Delhi,

R. KIRAN NATH, Pr. Secy. (Law, Justice & LA)

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 जुलाई, 2015

संख्या 161/8/शुल्क संरचना/डीडीटीई/2014—15/2376.—दिल्ली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थान (समानता एवं उत्कृष्टता सुनिष्वित करने हेतु केपिटेषन षुल्क प्रतिबंध, प्रवेष के विनियमन, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय) अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम 7) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त षित्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एतद्द्वार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संस्थान के पाट्यक्रमों के अध्ययन हेतु षुल्क निर्धारण के प्रयोजन से तथा उक्त अधिनियम में सौंपे गये प्रकार्यों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित स्ति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

शुल्क विनियामक समिति

1,	श्री जी. एस. पटनायक, भा० प्र० से० (सेवानिवृत्त)	_	अध्यक्ष
2.	श्री बी. एस. जैन, चार्टर्ड एकाउटेंट	_	सदस्य
3.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का प्रतिनिधि	*·	सदस्य
4.	गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति या उनका प्रतिनिधि	· <u>-</u>	सदस्य
5.	सचिव (प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग)	_	सदस्य सचिव (पदेन)

<u>टिप्पणी</u> — उपर्युक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष का होगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से और उनके नाम पर.

मनोज कुमार, निदेशक (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 31st July, 2015.

No.161/8/FEE STRUCTURE/DDTE/2014-15/2376.- In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 6 of the Delhi Diploma Level Technical Education Institutions (Prohibitation of Capitation fee, Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and other Measures to Ensure Equity and Excellence) Act , 2007, (Delhi Act-7 of 2007), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby constitutes the following committee for the purpose of determining fee for pursuing courses in an Institution in the National Capital Territory of Delhi and to perform the functions assigned to it in the said Act, consisting of the following members namely:-

Fee Regulatory Committee

(1)	Sh. G.S. Patnailk, IAS (Retd.)	Chairperson
(2)	Sh. B.S. Jain, Chartered Accountant	Member
(3)	Representative of All India Council of Technical Education	Member
(4)	Vice Chancellor of GGSIP University or his representative	Member
(5)	Secretary (Training and Technical Education Department)	Member Secretary
		(ex – officio)

Note: The terms of the Chairperson and the members of the above Committee shall be three years commencing from the date following this notification.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, MANOJ KUMAR, Director (Training and Technical Education)